ग्रामीण योजनाओं से खुलती विकास की संभावनाएं

भारत डोगरा

बाबा आमटे ने कहा था गांववासियों को दया नहीं चाहिए, उन्हें तो बस पर्याप्त अवसर चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में कई बार सही विकास व प्रगति के जो अवसर मौजूद हैं वे अवसर ही बहुत से निर्धन व उपेक्षित गांववासियों को नहीं मिल पाते हैं। यदि गांववासियों के सहयोग से गांव की विकास योजना बनाई जाए तो गांवों में छिपी हुई विकास की संभावनाएं सामने लाई जा सकती हैं व इन संभावनाओं के प्रति गांववासियों को अधिक सचेत व सक्रिय किया जा सकता है।

इस महत्वपूर्ण भूमिका को ओड़ीशा के कालाहांडी क्षेत्र में निभाया है सहभागी विकास अभियान व उससे जुड़े कई जन-संगठनों ने। कई वर्षों से क्षेत्र के चार ज़िलों कालाहांडी, नवापाड़ा, बढ़गढ़ व बोलनगीर में सक्रिय इस अभियान की विशेष सफलता छोटे किसानों की टिकाऊ आजीविका का आधार मज़बूत करने में रही है। स्वराज अभियान के अंतर्गत इस संस्था ने किसानों व गांवों की आत्म-निर्भरता बढ़ाने के सतत प्रयास किए हैं। इसके स्वराज ब्रांड के मसाले व अन्य उत्पाद स्थानीय बाज़ार में बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद लोकप्रिय हैं।

सहभागी के कार्यकर्ताओं की बड़ी पहचान गांववासियों की समस्याओं से नज़दीकी जुड़ाव के रूप में रही है। यही वजह है कि वे कई गांवों के पानी में फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा व इससे उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में प्रशासन को समय पर चेतावनी दे सके। इस जानकारी के आधार पर यह मांग उठाई गई कि गांवों में सुरक्षित पानी आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के अधिक उपयोग से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की ओर भी सहभागी ने बहुत ध्यान दिलाया है व विकल्प के तौर पर जैविक खेती के सफल प्रयोग करते हुए इसका प्रसार कई गांवों में किया है।

सहभागी विकास अभियान ने गांवों में किसान क्लबों का गठन किया है जो इन प्रयासों के लिए प्रयत्नशील है व साथ में किसानों को विभिन्न सरकारी स्कीमों, विशेषकर लघु सिंचाई स्कीमों की जानकारी भी देते रहते हैं जिससे इन स्कीमों का सार्थक उपयोग छोटे किसान व अन्य ज़रूरतमंद गांववासी कर सकें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण बचत व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है जबकि साहूकारों पर निर्भरता कम की गई है।

गांवों से बहुत नज़दीकी सरोकारों के आधार पर सहभागी विकास अभियान की यह सोच बढ़ी है कि पिछड़े व निर्धन गांवों के रूप में पहचाने जाने वाले कालाहांडी ज़िले के गांवों में भी सार्थक व टिकाऊ विकास की बहुत-सी संभावनाएं मौजूद हैं जो ठीक से व विस्तार से सामने नहीं आ सकी हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का बड़ा अवसर तब मिला जब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कालाहांडी क्षेत्र के विकास में सहभागी विकास अभियान के विशिष्ट योगदान को देखते हुए उसे एक विशेष अनुदान दिया गया। इस अनुदान का उपयोग सहभागी ने अनेक सार्थक कार्यों के लिए किया। जैसे कि आदिवासियों के भूमि अधिकार अभियान को मज़बूत करना। इस अनुदान का बहुत सार्थक उपयोग लगभग 500 गांवों की ऐसी विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए भी किया गया जिनसे इन गांवों के सार्थक व टिकाऊ विकास की संभावनाएं विस्तार से व स्पष्ट रूप से सामने आ सकीं।

सहभागी की वरिष्ठ कार्यकर्ता पांचाली ने बताया, 'विभिन्न गांवों के लोगों से संपर्क कर उनसे इस गांव योजना को तैयार करने के महत्व के बारे में चर्चा की गई। उन्हें बताया गया कि यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो दो या तीन कार्यकर्ताओं की एक टीम गांव में कुछ दिनों तक रहेगी व विभिन्न समूहों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। इन कार्यकर्ताओं के आवास व भोजन की व्यवस्था स्वयं गांववासियों को ही करनी होगी।'

इस तरह गांववासियों व कार्यकर्ताओं में आपसी समझ को बढ़ाने का भरपूर अवसर मिला। विभिन्न तरह की विकास की संभावनाओं को लोगों के सामने रखा गया व उनके परामर्श के अनुसार विभिन्न सुझावों को गांव की विकास योजनाओं में शामिल किया गया।

सहभागी विकास अभियान के संस्थापक जगदीश प्रधान बताते हैं, 'इस तरह की विस्तृत चर्चा से विकास की विभिन्न संभावनाओं के प्रति गांववासी अधिक सचेत और सक्रिय हो गए। बाद में अनुकूल अवसर उपलब्ध होने पर वे अधिक उत्साह और सक्रियता से आगे आए हैं।'

अब इनमें से अनेक गांवों में सार्थक विकास की महत्वपूर्ण पहल आरंभ भी हो चुकी है।

जगदीश प्रधान किसान आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। वे आगे बताते हैं, इन अनुभवों से हमारा विश्वास दृढ़ हुआ कि जिन गांवों को बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, वहां भी सार्थक विकास की काफी संभावनाएं छिपी होती हैं। आपसी भागीदारी से गांव विकास की योजना तैयार हो तो ये संभावनाएं स्पष्ट रूप से गांववासियों के सामने आ जाती हैं व वे इनके लिए अधिक प्रयत्नशील हो जाते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***